

भारत सरकार  
पोत परिवहन मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्ना सं. 1976 जिसका उत्तर  
गुरुवार, 10 दिसंबर, 2015/19 अग्रहायण, 1937 (शक) को दिया जाना है  
सागरमाला परियोजना

1976. श्री विद्युत महतो :

श्री दुष्यंत चौटाला :

क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने पोत- नीति आर्थिक विकास और तटीय आर्थिक क्षेत्रों के रूप में संभावित भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान के लिए सागरमाला परियोजना आरंभ की है/ आरंभ करने का प्रस्ताव है
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सागरमाला परियोजना के लिए पहचान किए गए पत्तखनों की संख्या कितनी है
- (ग) क्या सरकार का प्रस्ताव तटरेखा के साथ-साथ सस्तेक, गैर-प्रमुख पत्तलन स्थापित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है
- (घ) क्या, इस कदम से पत्तनों पर माल ढुलाई संचालन के अर्थों में अतिरिक्त क्षमता के साथ तटीय पोत परिवहन को प्रोत्साहन मिलेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य कया कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं

उत्तर

पोत परिवहन राज्यस मंत्री

(श्री पोन्. राधाकृष्णान्)

(क): जी, हाँ ।

(ख) से (घ) : पत्तन उन्मुखी विकास में पत्तन उन्मुखी औद्योगिकीकरण, पत्तन पर आधारित शहरीकरण, मौजूदा पत्तनों का आधुनिकीकरण तथा पत्तनों का विकास, मौजूदा तथा भविष्य की परिवहन परिसंपत्तियों का ईष्टतम उपयोग तथा परिवहन में लिए नए मार्ग/संयोजनों का विकास करना (इनमें सड़क, रेल, अंतर्देशीय जलमार्ग तथा तटीय मार्ग शामिल हैं), तटीय पर्यटन, मनोविनोद गतिविधियाँ, छोटा समुद्री नौवहन, तटीय नौवहन, पोत निर्माण, पोत मरम्मत पोत पुनःचक्रियकरण, लॉजिस्टिक्स पार्क, भंडारण, समुद्री ज़ोन/सेवाएँ आदि शामिल हैं। सागरमाला परियोजना के एक भाग के रूप में एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यत योजना (एन पी पी) तैयार की गई है जिसमें तटीय आर्थिक ज़ोन (सी ई ज़ेड) के रूप में संभाव्य युक्तर भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान किया जाना, तटरेखा के समानांतर महापत्तनों तथा गैर महापत्तनों की पहचान करना तटीय नौवहन आदि शामिल हैं।

\*\*\*\*\*